the specific understanding that their services would be terminated at short notice. The reversions and retrenchments became necessary as it was found that even after making all possible adjustments, about 800 employees were surplus to the requirement.

बुवाई के लिए गेहूं तथा चने के बीज की कमी

4008. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में किसानों को बोने के लिये गेहूं तथा चने के बीज उपलब्ध नहीं हो सके थे;

(ख) क्या सरकार को इस कमी की जानकारी थी; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की थी तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान में विपणन सोसायटियों अथवा अन्य सरकारी ऐजेंसियों ने तथा चने का बीज प्रति क्विंटल किस दर पर बेचा था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). बीजों की मांग का मूल्यांकन करने और उन के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था करने के लिये प्रमुखतः राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। किसी भी राज्य सरकार ने चने के बीजों की कमी की सूचना नहीं भेजी है। राजस्थान सरकार ने भारतीय राज्य फार्म निगम से 19,000 क्विंटल चने के बीजों की मांग की थी, जो उन्हें सप्लाई कर दी गई थी। जहां तक गेहूं के बीजों का सम्बन्ध है, कुछ राज्य सरकारों ने वर्षा होने से उत्पन्न हुई अनुकूल परिस्थितियों के कारण खेती के अन्तर्गत अतरिक्त क्षेत्र लाने के लिये गेहूं के बीजों की सप्लाई करने का अनुरोध किया था। कुछ राज्य रबी के गत मौसम में सूखे की स्थिति मौजूद होने के कारण अपने क्षेत्रों से अपनी मांग पूरी न कर सके। गेहूं के बीजों की सामान्य कमी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने बीज के रूप में उपयोग करने के लिये भारतीय खाद्य निगम से अच्छी किस्म के गेहूं के स्टाक की निम्नलिखित मात्रा नियुक्त करने के लिये व्यवस्था की थी :—

1. मध्य प्रदेश	3,000 मीटरी टन
2. गुजरात	3,000 मीटरी टन
3. राजस्थान	5,000 मीटरी टन
4. बिहार	5,000 मीटरी टन
5. असम	5,000 मीटरी टन

मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में विपणन समितियों अथवा अन्य सरकारी ऐजेंसियों ने गेहूं तथा चने का बीज कितने रु० प्रति क्विंटल की दर पर बेचा था, इस के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जंगलों को काटकर उस क्षेत्र को कृषि के लिए वितरित करना

4009. **श्री लालजी भाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सरकार ने वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान जंगलों को काट कर उस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया है; और

(ख) हरिजनों को ऐसी भूमि किस सीमा तक आवंटित की गई है ?